सदस्य बनें
सच और सरोकार की पत्रकारिता से जुड़ें
वार्षिक सदस्यता : ₹ 500 मात्र
पूरा वर्ष अख़बार नि:शुल्क
पैनल विज्ञापन दें
अपने व्यवसाय/संस्था का प्रचार करें 'जन जन विचार' में।
किफायती • प्रभावी • विश्वसनीय
संपर्क : 69001 26012

जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार

D.S. Associates
Sri Om Plaza
2nd Floor, K.C. Road,
Chatribari, Guwahati-1
Phone : 7002682705

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 22 May 2026 :: Vol-19 Year-1 :: शुक्रवार ।22 मई 2026। शक संवत 1948। ज्येष्ठ।शुक्ल ।षष्ठी।:: पृष्ठ-8 ।मूल्य - 5 रुपए

जन चिंतन
धनेश्वर चौधरी

भोजशाला का सच

धार की भोजशाला पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना है जिसे दशकों तक 'विवाद' कहकर दबाने की कोशिश की गई। अदालत ने स्पष्ट रूप से भोजशाला को मां वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर माना और उस व्यवस्था को निरस्त कर दिया, जिसके तहत वहां नमाज की अनुमति दी गई थी।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार अदालत ने केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऐतिहासिक दस्तावेजों, स्थापत्य प्रमाणों और अभिलेखों को आधार बनाकर अपना निर्णय दिया। 98 दिनों तक चले सर्वे में मंदिरनुमा संरचनाएं, संस्कृत शिलालेख, देवी-देवताओं से जुड़े अवशेष और परमारकालीन स्थापत्य के प्रमाण सामने आए। एएसआई ने अदालत को बताया कि परिसर में मौजूद ढांचे मंदिर के अवशेषों पर निर्मित थे।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि इतने स्पष्ट प्रमाण वर्षों से मौजूद थे, तो सत्य को स्वीकार करने में इतनी देर क्यों लगी? इसका उत्तर भारत की उस राजनीतिक **शेष पृष्ठ 2 पर**

'पूर्वी हिंदुत्व त्रिमूर्ति'

हिंदुत्व, सुशासन और आक्रामक राष्ट्रवाद से बदला राजनीतिक विमर्श

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी-ये तीन नाम आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उस नई और आक्रामक राजनीतिक शैली के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं, जो न केवल चुनावों की दिशा बदल रही है, बल्कि देश के जनमानस को भी गहराई से प्रभावित कर रही है।

हिंदी पट्टी के दिल उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार असम और बंगाल की खाड़ी के राजनीतिक अखाड़े तक, इन तीनों नेताओं की कार्यशैली में एक अनूठा तालमेल दिखता है। यह 'त्रिमूर्ति' आज के भारत की राजनीति को नया आकार दे रही है।

योगी आदित्यनाथ :'बुलडोजर मॉडल'

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और कभी 'बीमारू' कहे जाने वाले राज्य में योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और कानून-व्यवस्था की एक नई परिभाषा लिखी है। उनके 'बुलडोजर मॉडल' को आज देश के कई अन्य राज्य भी कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए एक नजीर के रूप में देख रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से लेकर काशी और मथुरा के कायाकल्प तक, योगी ने विकास को सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़ दिया है। जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे 'कड़े और ईमानदार' प्रशासक की है, जो तुष्टिकरण के बजाय 'सबका साथ, सबका विकास' लेकिन बिना किसी समझौते के, पर विश्वास रखता है।

हिमंत : पूर्वोत्तर की पहचान और सुरक्षा के प्रहरी

पूर्वोत्तर की राजनीति को उग्रवाद और अस्थिरता से निकालकर मुख्यधारा के विकास से जोड़ने का श्रेय काफी हद तक डॉ. हिमंत विश्व शर्मा को जाता है। जनसांख्यिकीय संतुलन और स्थानीय असमिया संस्कृति की रक्षा के लिए हिमंत के कड़े फैसलों ने उन्हें देशव्यापी पहचान दिलाई है। वे केवल असम के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और 'ट्रबलशूटर' हैं। असमिया अस्मिता और राष्ट्रवाद के मुखर मिश्रण के कारण युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। वे नीतिगत फैसलों में बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं।

सनातन विरोध पर सिमटी विपक्ष की राजनीति

गुवाहाटी। देश की राजनीति में सनातन विरोध अब कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सीधे चोट पहुंचाई। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं के निशाने पर बार-बार केवल सनातन धर्म ही आता है? क्या यह सब वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा है?

तमिलनाडु **शेष पृष्ठ 3 पर**

आज विपक्ष का हर नेता परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सनातन के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मूक समर्थक भी बना हुआ है।

सुभेंदु अधिकारी : आक्रामक हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सुवेंदु अधिकारी एक आक्रामक हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराकर और भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दिलाकर शुभेंदु ने बंगाल की राजनीति का पूरा सत्ता समीकरण बदल दिया। भाजपा ने 294 में 207 सीटें जीतकर 15 साल पुराने तृणमूल शासन का अंत किया और शुभेंदु बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने।

कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल में 'कट मनी', 'सिंडिकेट राज' और 'तुष्टिकरण राजनीति' के खिलाफ सबसे मुखर चेहरे के रूप में सामने आए हैं। **शेष पृष्ठ 3 पर**

यह 'त्रिमूर्ति' भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व (मोदी-शाह) की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जहां नेताओं को उनके कड़े और बेबाक फैसलों के लिए खुली छूट दी जाती है। कठोर सच यह है कि अब भाजपा केवल चुनावी जीत से संतुष्ट नहीं है। योगी, हिमंत और सुवेंदु के जरिए पार्टी राज्यों के प्रशासनिक ढांचे, कानूनी ढांचे और जनसांख्यिकीय हकीकत को स्थायी रूप से बदल रही है। पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैला यह 'कठोर राष्ट्रवाद' और 'तुष्टिकरण विरोधी' मॉडल अब देश की मुख्यधारा की राजनीति का नया पैमाना बन चुका है। जो विपक्ष कल तक इन्हें सिर्फ 'चुनावी ध्रुवीकरण' का चेहरा बताता था, आज वह इन तीनों मुख्यमंत्रियों के कड़े प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों के सामने अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक कदम

गुवाहाटी में एथेना ने खोला पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा केंद्र

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

पूर्वोत्तर में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और नशे की लत के बीच गुवाहाटी में एथेना बिहेवियरल हेल्थ के सबसे बड़े एकीकृत निजी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल का उद्घाटन किया गया। गड़चुक स्थित इस केंद्र में मानसिक रोग उपचार, नशामुक्ति, साइकोथेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार असम में लगभग 8 प्रतिशत लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में इस अस्पताल को क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे के लिए बड़ी पहल माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वोत्तर में अवसाद, चिंता, आत्महत्या और नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि संगठित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी बनी हुई है।

एथेना बिहेवियरल हेल्थ की संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रद्धा मलिक ने कहा कि गुवाहाटी केंद्र का उद्देश्य कम सुविधायुक्त क्षेत्रों तक उच्चस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। वहीं आईएचबीएएस के पूर्व निदेशक डॉ. निमेश जी देसाई ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि सुलभ और मानवीय उपचार व्यवस्था भी बेहद जरूरी है।

अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। यह केंद्र सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुला रहेगा।

गुवाहाटी से युवक लापता, परिवार चिंतित

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

महानगर के बेलतला तिनिआली क्षेत्र निवासी बसंत कुमार जम्मड़ पिछले दो हफ्तों से लापता हैं। जानकारी के अनुसार, वह 11 मई को घर से बिना कुछ बताए निकल गए थे, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

परिवारजनों ने बताया कि बसंत कुमार जम्मड़ मानसिक और शारीरिक

रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे। पिछले कई दिनों से परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।

लापता युवक के पिता का नाम दिलीप कुमार जम्मड़ बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो परिवार ने तुरंत संपर्क करने की अपील की है। उनके भाई अवकाश कुमार जम्मड़ (9864970531) से संपर्क किया जा सकता है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

भोजशाला का सच

मानसिकता में छिपा है जिसने लंबे समय तक हिंदू आस्था से जुड़े हर प्रश्न को 'सांप्रदायिकता' कहकर दबाने की कोशिश की। राम जन्मभूमि से लेकर काशी और अब भोजशाला तक-हर बार हिंदुओं को अपने ही इतिहास के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े।

विडंबना देखिए, जैसे ही अदालत ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया, कुछ तथाकथित सेक्युलर नेताओं और संगठनों को इसमें भी 'खतरा' दिखाई देने लगा। किसी ने फैसले को 'वाग' बताया, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास का सच अदालत के फैसलों से बदला जा सकता है? क्या संस्कृत शिलालेख, टूटी मूर्तियां और मंदिर स्थापत्य केवल कल्पना हैं?

भोजशाला का फैसला यह भी साबित करता है कि भारत की सांस्कृतिक स्मृति को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। सदियों के आक्रमण, राजनीतिक समझौते और वैचारिक दबाव के बावजूद सत्य आखिर सामने आता ही है। यही कारण है कि यह निर्णय केवल धार तक सीमित नहीं रहा; काशी, मथुरा और देशभर के संत समाज में इसे सांस्कृतिक न्याय की दिशा में बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

स्पष्ट होना चाहिए-यह किसी समुदाय के खिलाफ संघर्ष नहीं है। यह उस ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ आवाज है, जिसमें भारत की मूल सभ्यता के प्रतीकों को मिटाकर उन्हें 'विवादित ढांचा' बना दिया गया। यदि किसी राष्ट्र को अपने भविष्य को मजबूत करना है, तो उसे अपने अतीत के सत्य को स्वीकार करना ही होगा।

भोजशाला का फैसला बताता है कि भारत अब अपने इतिहास को केवल पाठ्यपुस्तकों की नजर से नहीं, बल्कि सभ्यतागत दृष्टि से देखना शुरू कर चुका है। यह उस नए भारत का संकेत है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करना चाहता है, माफी नहीं मांगना चाहता। सदियों बाद इतिहास ने फिर कहा है-सत्य दब सकता है, पर हारता नहीं।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता शिविर

गुवाहाटी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 'ट्रू हेल्थ सेमिनार' नामक स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन इवेंट्स इनफिनिटी द्वारा 31 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक नीलगिरी अपार्टमेंट, भांगागढ़ स्थित कार्यालय में किया जाएगा।

सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में रूपक देव और ज्योतिर्मय हजारिका उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की मेजबानी एक्टर अक्की अवकाश जैन जम्मड़ करेंगे।

सेमिनार का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए प्रेरित करना है। जानकारी के लिए 9864970531 पर संपर्क किया जा सकता है।

साप्ताहिक राशिफल

22 मई से 28 मई 2026 ।। विक्रम संवत 2083-**मास** : ज्येष्ठ, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** : षष्ठी

मेष — **इस** सप्ताह करियर में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें। रिश्तों में जल्दबाज़ी से बचें।

वृषभ — **धन** और परिवार के मामलों में स्थिरता रहेगी। नौकरी या बिज़नेस में रुका काम आगे बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य में आलस्य से बचें।

मिथुन — **यह** सप्ताह आपके लिए काफी सक्रिय रहेगा। नए लोगों से संपर्क लाभ देगा। करियर में प्रशंसा मिल सकती है। अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है।

कर्क — **भावनात्मक** उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा।

सिंह — **आत्मविश्वास** बढ़ेगा और सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में स्पष्ट बातचीत जरूरी है।

कन्या — **काम** का दबाव बढ़ सकता है लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर पेट संबंधी समस्या से सावधान रहें। धन लाभ के संकेत हैं।

तुला — **रिश्तों** में संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह जरूरी रहेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

वृश्चिक — **इस** सप्ताह निर्णय सोच-समझकर लें। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव कम करने के लिए आराम करें।

धनु — **भाग्य** का अच्छा साथ मिलेगा। शिक्षा, यात्रा और करियर में प्रगति होगी। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मकर — **कामकाज** में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन लाभ भी मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है।

कुंभ — **रचनात्मक** कार्यों में सफलता मिलेगी। नई योजनाएँ शुरू करने के लिए अच्छा समय है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

मीन — **भावनात्मक** रूप से संवेदनशील रह सकते हैं। घर-परिवार में समय देना लाभकारी रहेगा। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

26 मई (मंगलवार) : गंगा दशहरा
27 मई (बुधवार) : पुरुषोत्तम एकादशी
28 मई (वृहस्पतिवार) : प्रदोष व्रत

भाग्योदय Bhagyoday Astrology
●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

असम सरकार ने खर्चों पर कसा शिकंजा

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच असम सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च कटौती अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी विभागों, जिला प्रशासन और सरकारी निकायों को चालू वित्त वर्ष के दौरान नियमित एवं प्रशासनिक खर्च में 10 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया है।

वित्त आयुक्त एवं सचिव जयंत नारलीकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाले पेट्रोल, डीजल, तेल और लुब्रिकेंट्स पर होने वाले खर्च में 20 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन काफिलों को भी सीमित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अनावश्यक ईंधन खर्च को रोका जा सके। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ऋण भुगतान और अन्य अनिवार्य वित्तीय दायित्वों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार ने विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने और साझा परिवहन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन और कार-पूलिंग का उपयोग करने को कहा गया है। परिवहन विभाग को राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और इसके लिए प्रोत्साहन नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

नई नीति के तहत शहरी निकायों और सरकारी कार्यालयों को बिजली की खपत कम करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिए नियमित ऊर्जा ऑडिट कराए जाएंगे और अनावश्यक बिजली उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निकायों को विशेष रूप से स्ट्रीट लाइटों और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली बिजली की बर्बादी रोकने को कहा गया है।

सरकार ने अगले छह महीनों तक मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगाने का भी फैसला किया है। केवल राष्ट्रीय हित, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आपातकाल या विदेश में रह रहे निकट संबंधियों से जुड़े मामलों में ही मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति से यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

चुनाव से पहले जुटे थे, हार के बाद गायब

जुबिन क्षेत्र से विपक्ष पर हिमंत का तंज

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने 20 मई को सोनापुर स्थित जुबिन गर्ग के समाधि स्थल 'जुबिन क्षेत्र' का दौरा कर विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला।

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले कई विपक्षी नेता जुबिन क्षेत्र पहुंचे थे, लेकिन हार के बाद उनमें से कोई वापस नहीं आया। उन्होंने कहा, 'चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन हारने के बाद सब गायब हो गए।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के दिल में जुबिन गर्ग का हमेशा विशेष स्थान रहेगा तथा कलाकारों को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान जुबिन गर्ग को राजनीतिक नैरेटिव में शामिल करने की कोशिश की, जिसका उल्टा असर पड़ा।

हिमंत ने दावा किया कि जुबिन गर्ग को लेकर की गई राजनीति के कारण भाजपा को हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 प्रतिशत अधिक वोट मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह जुबिन गर्ग का राजनीतिकरण नहीं करेगी और जनता ने भी इस निर्णय को सही साबित कर दिया।

असम साहित्य सभा के आजीवन सदस्य रामेश्वर चुंडी का निधन

माजबाट। माजबाट के नमाटी ख (लाचितनगर) निवासी तथा रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक, माजबाट प्राथमिक शिक्षक समूह के पूर्व सचिव और माजबाट शतदल साहित्य सभा के आजीवन सदस्य रामेश्वर चुंडी का गत 18 मई की सुबह लगभग 4 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।

उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। उनके आवास पर पहुंचकर बीटीसी के पार्षद श्याम चुंडी, पूर्व पार्षद जितु किशान और दीपक मौर सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पीछे वे पत्नी, पुत्र, बहू और नातिन को छोड़ गए हैं। पाचनैखुटी के नव-निर्मित श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

उनके निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक व्यक्त किया है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

सुभेंदु अधिकारी : आक्रामक हिंदुत्ववादी...

मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में अब 'सिस्टमेटिक चेंज' होगा और भ्रष्टाचार व राजनीतिक संरक्षण की राजनीति खत्म की जाएगी।

शुभेंदु सरकार का सबसे आक्रामक कदम अवैध घुसपैठ और सीएए को लेकर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने 'डिटेक्ट, डिलिट, डिपोर्ट' अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि जो घुसपैठिए सीएए के दायरे में नहीं आते, उन्हें चिह्नित कर बीएसएफ को सौंपा जाएगा। इस बयान ने बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी।

समर्थकों के लिए शुभेंदु अधिकारी अब 'हिंदू अस्मिता' और 'राष्ट्रवादी बंगाल' के प्रतीक बन चुके हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने के बाद उन्होंने खुलकर कहा था कि उन्हें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समाज का समर्थन मिला। इस बयान ने बंगाल की राजनीति को सीधे वैचारिक ध्रुवीकरण की दिशा में पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु ने एक ओर 7वां वेतन आयोग, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और 'अन्नपूर्णा भंडार' जैसी योजनाओं का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद को अपनी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनाने की कोशिश की है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी अब केवल भाजपा नेता नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में आक्रामक हिंदुत्व राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को भाजपा के 'पूर्वी हिंदुत्व त्रिमूर्ति' के रूप में भी देखा जाने लगा है, जो बंगाल से लेकर असम और उत्तर प्रदेश तक राष्ट्रवादी राजनीति की नई धारा को मजबूत कर रहे हैं।

सनातन विरोध पर सिमटी विपक्ष की राजनीति

के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना 'डेंगू और मलेरिया' जैसी बीमारियों से करते हुए कहा था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। इस बयान ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा किया। इसके बाद डीएमके नेता ए. राजा ने भी सनातन धर्म को सामाजिक भेदभाव से जोड़कर विवाद खड़ा किया। आलोचकों का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि एक सोची-समझी वैचारिक राजनीति का हिस्सा है।

कांग्रेस पर भी लंबे समय से हिंदू भावनाओं की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भले ही चुनावी मंचों पर मंदिर दर्शन करते दिखाई देते हों, लेकिन उनके कई बयान और पार्टी नेताओं की टिप्पणियां लगातार विवादों में रही हैं। 'हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म' वाला उनका बयान राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बना था। आलोचकों का आरोप है कि कांग्रेस एक तरफ हिंदू वोट चाहती है, दूसरी तरफ हिंदुत्व और सनातन पर सवाल उठाने वालों पर कभी कठोर रुख नहीं अपनाती।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा 'भगवा आतंकवाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज भी हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को आहत करता है। वहीं शशि थरूर के कुछ बयानों को भी हिंदू परंपराओं के प्रति उपेक्षापूर्ण माना गया।

समाजवादी पार्टी में भी सनातन विरोधी बयानों को लेकर विवाद कम नहीं रहे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और सनातन परंपराओं पर लगातार विवादित टिप्पणियां कीं। उन्होंने हिंदू ग्रंथों के अंश हटाने तक की मांग कर डाली। विपक्ष का आरोप है कि सपा नेतृत्व ने वोट बैंक की राजनीति के कारण उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव पर भी हिंदू मुद्दों पर 'चयनात्मक चुप्पी' के आरोप लगते रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर कई बार रामनवमी शोभायात्राओं और हिंदू धार्मिक आयोजनों के प्रति कठोर रवैया अपनाने के आरोप लगे। आलोचकों का कहना है कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण हिंदू आस्था से जुड़े मामलों में दोहरा मापदंड अपनाया जाता है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नेता किसी अन्य धर्म के खिलाफ ऐसी भाषा बोलने का साहस दिखा सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है-नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज सहिष्णु है और लंबे समय तक चुप रहता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। देशभर में सनातन और हिंदू आस्था के अपमान के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिंदू समाज अब यह समझने लगा है कि सनातन विरोध केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि हर चुनाव में जनता ऐसे बयानों का हिसाब मांगने लगी है।

भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति से है। जो नेता इस संस्कृति को अपमानित करेंगे, उन्हें लोकतंत्र में जनता के कठोर फैसले का सामना करना पड़ सकता है।

संपादकीय

आवारा कुत्तों पर सरकारों की परीक्षा

देश में आवारा कुत्तों का आतंक अब केवल असुविधा नहीं, बल्कि गंभीर जनसुरक्षा संकट बन चुका है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का घर से निकलना तक मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी, खतरनाक कुत्तों को हटाने और जरूरत पड़ने पर इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाला फैसला करोड़ों लोगों को राहत की उम्मीद जरूर देता है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल आदेश देने भर से हालात बदल जाएंगे? देश में कानून और आदेशों की कमी नहीं, कमी है जिम्मेदारी तय करने की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के छह महीने बाद भी कई राज्यों में डॉग सेंटर तक नहीं बने। दिल्ली, गाजियाबाद और कई बड़े शहरों में फाइलें घूम रही हैं, जबकि सड़कों पर लोग रोज कुत्तों का शिकार बन रहे हैं।

स्थिति भयावह है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में देश में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में यह संख्या 47 लाख पार कर गई। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में हर साल हजारों लोग रेबीज से मरते हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक संवेदनहीनता जारी है।

सच्चाई यह है कि जब तक हर जिले के डीएम और नगर निकायों को सीधे जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। पशु प्रेम के नाम पर सड़कों पर कुत्तों को बढ़ावा देना भी समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। मानव जीवन सर्वोपरि है और सरकारों को यह स्पष्ट संदेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है, अब परीक्षा सरकारों और प्रशासन की है।

सुलगता सवाल ? आपके विचार

अब 2027 की जंग

पश्चिम बंगाल और असम में शानदार जीत के बाद भाजपा अब 2027 के चुनावी रण की तैयारी में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में सत्ता बचाना भाजपा के लिए केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होगी। खासकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश इस पूरे चुनावी युद्ध का केंद्र बनने जा रहा है।

भाजपा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह चुनाव को अभियान नहीं, मिशन की तरह लड़ती है। एक चुनाव खत्म होते ही अगली रणनीति शुरू हो जाती है। यही कारण है कि पार्टी अभी से बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में अपेक्षा से कम प्रदर्शन के बाद भाजपा नेतृत्व कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा।

दूसरी ओर विपक्ष अभी भी स्पष्ट नेतृत्व और एजेंडे के संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस कई राज्यों में संगठन बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि क्षेत्रीय दल अपने-अपने अस्तित्व में उलझे हैं। ऐसे में भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेगी।

स्पष्ट है कि 2027 केवल विधानसभा चुनाव नहीं होगा, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल साबित होगा। भाजपा के लिए यह सत्ता बचाने की लड़ाई है, जबकि विपक्ष के लिए अस्तित्व बचाने की।

तो कैसे आएगी एका

जन जन विचार
...✍ उमेश चतुर्वेदी

विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी हैं।

दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिरे से परवान चढ़ सकता है? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ, लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाए। लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले ही ना हो, लेकिन अगुवाई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराशा में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिनसे वे दूर हो चुके थे। इसके बाद का इतिहास सबको पता है।

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है।

गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्ष बह जाता है, उसकी एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। ज्यादातर यह अस्तित्व संकट टालने का यह फौरी उपाय होता है। तब वह हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुट जाता है। फिर उसे इलहाम होता है कि अगर वह एक रहता तो वह भारी पड़ता। 1962 के आम चुनावों में नेहरू को फूलपुर की सीट पर सीधी चुनौती में हार मिलने के बाद लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। तब भारी उत्सुकता और उत्साह के बावजूद लोहिया हार गए थे। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को 44 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्ष की एकता के सुर उठने की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वाममोर्चा और जनसंघ- भाजपा भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है।

प. बगाल के बीते विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं भाजपा को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वाममोर्चे को 4.45 प्रतिशत वोट मिले हैं। गैर भाजपा वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। अब विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो भाजपा को ऐसी जीत नहीं मिलती। वैसे चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा को पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में वह पिछड़ गई थी। चुनावी मैदान में जब सिर्फ दो खेमे होते हैं, तब मतदाताओं के बीच लंबवत ध्रुवीकरण हो जाता है। तब बिखराव वाले आंकड़े भी बदल जाते हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिखा, जब भाजपा सब पर भारी रही।

मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा चेहरा है भी नहीं। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य चेहरा मानने के राह की बड़ी बाधा है। राहुल मोदी-शाह की जोड़ी को चाहे जिस अंदाज में चुनौती दें, मोदी विरोधी बौद्धिकों को उनका यह अंदाज चाहे जितना भी पसंद हो, लेकिन आमजन को उनमें कई बार बचकानापन नजर आता है तो कई मर्तबा प्रहसन। स्टालिन चाहे जितनी अच्छी तमिल बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर स्वीकार्यता के लिए वे अयोग्य हैं। इसी तरह केजरीवाल के पास बड़ा आधार नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की तो, वे भी जमीनी राजनीति के बजाय बयानों के गुब्बारे उड़ाने के उस्ताद होते गए हैं।

आपसी अहं के टकराव के चलते नीतीश विपक्षी खेमा छोड़ चुके हैं। दूसरी बड़ी नेता ममता को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त मिल गई है। अखिलेश को भी अगले साल उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में भाजपा से दो-दो हाथ करना है। भाजपा की कोशिश उन्हें तीसरी बार शिकस्त देने की होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रही तो उसके सामने दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे का संकट बड़ा है। अतीत के विपक्षी व्यवहार से नहीं लगता कि शायद ही भविष्य में कोई मजबूत मोर्चा बन सके।

सुपर अल नीनो : तबाही की ओर बढ़ रहा भारत

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारत इस समय केवल गर्मी नहीं झेल रहा, बल्कि एक संभावित जलवायु आपदा की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और विदर्भ तक धरती तवे की तरह तप रही है। लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी इससे भी ज्यादा डराने वाली है। प्रशांत महासागर में तेजी से आकार ले रहा 'सुपर अल नीनो' आने वाले महीनों में भारत समेत पूरी दुनिया को भयावह संकट में धकेल सकता है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह सामान्य अल नीनो नहीं, बल्कि 'सुपर अल नीनो' बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यदि समुद्र की सतह का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो यह 1877 के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है, जब भयंकर सूखे और अकाल ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय वैश्विक आबादी के लगभग 4 प्रतिशत लोगों की मौत तक दर्ज हुई थी। अब 150 साल बाद वैसा ही खतरा फिर मंडरा रहा है।

भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानसून पर पड़ने वाला असर है। देश की करीब 70 प्रतिशत बारिश दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है और 60 प्रतिशत किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। अल नीनो मजबूत हुआ तो मानसून कमजोर पड़ेगा, बारिश कम होगी और खेत सूखने लगेंगे। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन, सब्जियों की कीमत, बिजली संकट और महंगाई पर पड़ेगा। यानी यह केवल मौसम की खबर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई तक पहुंचने वाला संकट है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है, जबकि दक्षिण और तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा रहेगा। यानी एक तरफ खेत सूखेंगे, दूसरी तरफ शहर डूबेंगे। चेन्नई, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है।

स्थिति इसलिए भी भयावह मानी जा रही है क्योंकि शहर पहले ही 'हीट आइलैंड' बन चुके हैं। कंक्रीट के जंगल, एसी से निकलती गर्मी, वाहनों का धुआं और हरियाली की कमी ने तापमान को और खतरनाक बना दिया है। यही कारण है कि रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही।

अमेरिकी एजेंसी एनओओ ने मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो बनने की 82 प्रतिशत संभावना जताई है, जबकि दिसंबर 2026 तक इसके बने रहने की आशंका 96 प्रतिशत बताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि दुनिया अभी तक जलवायु परिवर्तन को लेकर केवल सम्मेलनों और भाषणों में उलझी हुई है, जबकि खतरा अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। यदि समय रहते जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बनाया गया, तो आने वाले वर्षों में गर्मी, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती हैं।

सवाल अब केवल यह नहीं कि गर्मी कितनी बढ़ेगी, बल्कि यह है कि क्या भारत इस 'जलवायु युद्ध' के लिए तैयार भी है?

अमेरिका में भारतीयों के लिए नया संकट

नई दिल्ली। कभी भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका जाना सफलता, ऊंची सैलरी और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब वही 'अमेरिकन ड्रीम' हजारों भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए डर और असुरक्षा का कारण बनता जा रहा है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में छंटनी की नई लहर ने एच-1बी वीजा पर काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की जिंदगी हिला दी है।

मेटा, अमेजन और लिंक्डइन जैसी कंपनियों में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण कंपनियां पारंपरिक कोडिंग और सपोर्ट भूमिकाएं कम कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ा है, क्योंकि अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है।

अमेरिकी नियमों के अनुसार नौकरी जाने के बाद एच-1बी वीजा धारकों के पास केवल 60 दिनों का समय होता है। इस अवधि में उन्हें नई नौकरी ढूंढकर नया प्रायोजक हासिल करना होता है, वरना कानूनी रूप से अमेरिका छोड़ना पड़ता है।

लाहौर से बैठा 'लंगड़ा' चला रहा था आतंकी ऑपरेशन

पहलगाम हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट ने पाकिस्तान के चेहरे से एक बार फिर नकाब हटा दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि पूरी साजिश पाकिस्तान से रची गई और लाहौर में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट्ट उर्फ 'लंगड़ा' आतंकियों को सीधे निर्देश दे रहा था।

एनआईए के अनुसार इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ यानी 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने मिलकर अंजाम दिया। चार्जशीट में बताया गया है कि हमले से पहले 15 और 16 अप्रैल को आतंकियों ने बैसरन घाटी में रेकी की थी। स्थानीय मददगारों परवेज और बशीर अहमद ने पाकिस्तानी आतंकियों को ठिकाने, रास्ते और अन्य सहायता उपलब्ध कराई।

जांच एजेंसी ने तकनीकी और डिजिटल सबूतों के आधार पर साबित किया है कि हमला पूरी तरह पाकिस्तान से नियंत्रित हो रहा था। आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल फोन लाहौर और कराची से खरीदे गए थे। हमले के दौरान लाहौर से रियल-टाइम लोकेशन, भागने के रास्ते और निर्देश भेजे जा रहे थे।

एनआईए ने यह भी खुलासा किया कि हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क ने 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' का झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। टीआरएफ ने पहले टेलीग्राम चैनल पर हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर बयान बदल दिया।

रुपए की रक्षा के लिए आरबीआई होगा सख्त

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपए ने अब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों की चिंता बढ़ा दी है। रुपए की कीमत गिरकर 97 प्रति डॉलर के करीब पहुंचने के बाद आरबीआई सख्त कदम उठाने के मूड में दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बैंक रुपए को संभालने के लिए '3 इन 1 प्लान' पर काम कर रहा है, जिसमें ब्याज दर बढ़ाना, करेंसी स्वैप बढ़ाना और विदेशों से डॉलर जुटाना शामिल है।

सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ सकता है। यदि आरबीआई जून की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरें बढ़ाता है, तो होम लोन, वाहन लोन और कारोबारी कर्ज महंगे हो जाएंगे। यानी ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम परिवारों की कमर तोड़ रही है, ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा समेत शीर्ष अधिकारियों ने लगातार कई बैठकें कर स्थिति की समीक्षा की है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने के लिए अनिवासी भारतीयों से डॉलर जमा योजनाओं के जरिए बड़ी राशि जुटाने पर भी विचार कर रहा है।

साप्ताहिक
जन जन विचार
जन जन की बात जन जन तक
RNI Regd No. ASMUL/25/A2367

Head Office : Golapi Market, 1st Floor, Beltola, Guwahati 781029
Branch Office : JanJan Vichar, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Contact : 69001 26012
Email: official.janjanvichar@gmail.com
Website: WWW.janjanvichar.in

ग्राहक सदस्यता फॉर्म

ग्राहक विवरण

पूरा नाम : .....
पूरा पता : .....
.....
मोबाइल : ..... ह्वाट्सएप .....
ई-मेल (यदि हो) : .....

सदस्यता विवरण
अवधि : 1 वर्ष शुल्क : रु. 500/- मात्र

सदस्यता के साथ विज्ञापन लाभ
- सालभर (52 अंक) का अखबार निःशुल्क मिलेगा
- एक निःशुल्क विज्ञापन (10 सेमी. x 3 कॉलम)
- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ग्राहक की सुविधा अनुसार

भुगतान विवरण
☐ यूपीआई ☐ बैंक ट्रांसफर
Bank Details
JAN JAN VICHAR
Bank : HDFC, Branch : Guwahati
A/C No. 50200116979015
IFSC : HDFC0000264
इस क्यूआर कोड को स्कैन कर जन जन विचार के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर सकते हैं।
(कृपया उपरोक्त में किसी एक माध्यम से ही भुगतान करें।)
भुगतान तिथि : ..... रसीद संख्या: .....

घोषणा
मैं स्वेच्छा से जन जन विचार साप्ताहिक अखबार की एक वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता/करती हूँ एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर : तिथि :

कार्यालय उपयोग हेतु
सदस्यता क्रमांक: ..... भुगतान प्राप्त रसीद संख्या: ..... प्राप्तकर्ता का नाम : .....
तिथि : ..... हस्ताक्षर : .....

बच्चों के चाचा नेहरू

27 मई को पुण्यतिथि

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से 'चाचा नेहरू' कहते थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों के प्रति उनके विशेष स्नेह के कारण ही हर वर्ष 14 नवंबर को 'बाल दिवस' मनाया जाता है।

चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। वे कहते थे कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और अवसर मिलें, तो देश मजबूत बनता है। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा और विज्ञान को बहुत महत्व दिया। उनके समय में कई बड़े शिक्षण संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना हुई।

नेहरू जी को बच्चों के बीच जाना बहुत पसंद था। वे अक्सर बच्चों से हंसते-मुस्कुराते हुए बातें करते थे। बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। उनकी जैकेट पर लगा लाल गुलाब भी बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उन्हें गुलाब का फूल बहुत प्रिय था।

स्वतंत्रता आंदोलन में भी नेहरू जी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा।

27 मई 1964 को चाचा नेहरू का निधन हो गया, लेकिन बच्चों के प्रति उनका प्रेम और देश के लिए उनके सपने आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं।

राजा राममोहन राय, जिन्होंने बदली भारत की सोच

राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। वे महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक थे।

राजा राममोहन राय ने समाज में फैली कई बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय सती प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता था। राजा राममोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।

वे महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है, जब महिलाओं को सम्मान और शिक्षा मिले। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया।

राजा राममोहन राय ने 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करना था। वे धार्मिक सहिष्णुता और मानवता में विश्वास रखते थे।

उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।

27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देते हैं।

12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 394 पदों पर होगी नियुक्ति

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एनडीए एवं एनए-II परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। देश सेवा का सपना देखने वाले 12वीं पास युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में कुल 394 पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 9 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर भर्ती ?

भर्ती के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना तथा नौसेना अकादमी के विभिन्न पद शामिल हैं। सबसे अधिक 208 पद एनडीए आर्मी के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं वायुसेना फ्लाइंग शाखा में 92 पदों पर भर्ती होगी।

कौन कर सकता है आवेदन ?

सेना शाखा के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है।

नौसेना और वायुसेना के लिए 12वीं में पीसीएम (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित) विषय अनिवार्य है।

आयु सीमा

उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होना चाहिए। इस परीक्षा में किसी भी वर्ग को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी ?

चयन दो चरणों में होगा—

लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा में गणित तथा सामान्य योग्यता परीक्षा (जीएटी) शामिल होगी। दोनों पेपर मिलाकर कुल 900 अंक होंगे। **एसएसबी इंटरव्यू :** इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू भी 900 अंकों का होगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। महिला उम्मीदवारों तथा आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट दी गई है।

कैसे करें आवेदन ?

उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन शुरू : जारी
अंतिम तिथि : 9 जून 2026
परीक्षा तिथि : 13 सितंबर 2026

10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 899 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि कई पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती ?

भर्ती के तहत ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सकैवेटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन समेत कई पद शामिल हैं।

योग्यता क्या चाहिए ?

ड्राफ्ट्समैन : 12वीं के साथ ड्राफ्ट्समैनशिप या संबंधित ट्रेड में प्रमाणपत्र। **हिंदी टाइपिस्ट :** 12वीं पास और हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट। **स्टोर कीपर टेक्निकल :** 12वीं पास। **ऑपरेटर कम्युनिकेशन :** 10वीं पास और आईटीआई प्रमाणपत्र। **इलेक्ट्रीशियन :** 10वीं पास, आईटीआई तथा संबंधित अनुभव। **ओईएम पद :** भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और अनुभव आवश्यक।

आयु सीमा : उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

कितना मिलेगा वेतन ?

अधिकांश पदों पर वेतनमान 5200-20200 रुपए के साथ ग्रेड पे दिया जाएगा। ड्राफ्ट्समैन पद पर अधिक ग्रेड पे का लाभ मिलेगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 50 रुपए रखा गया है। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में छूट मिल सकती है।

कैसे करें आवेदन ?

इच्छुक उम्मीदवार बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज, फोटो

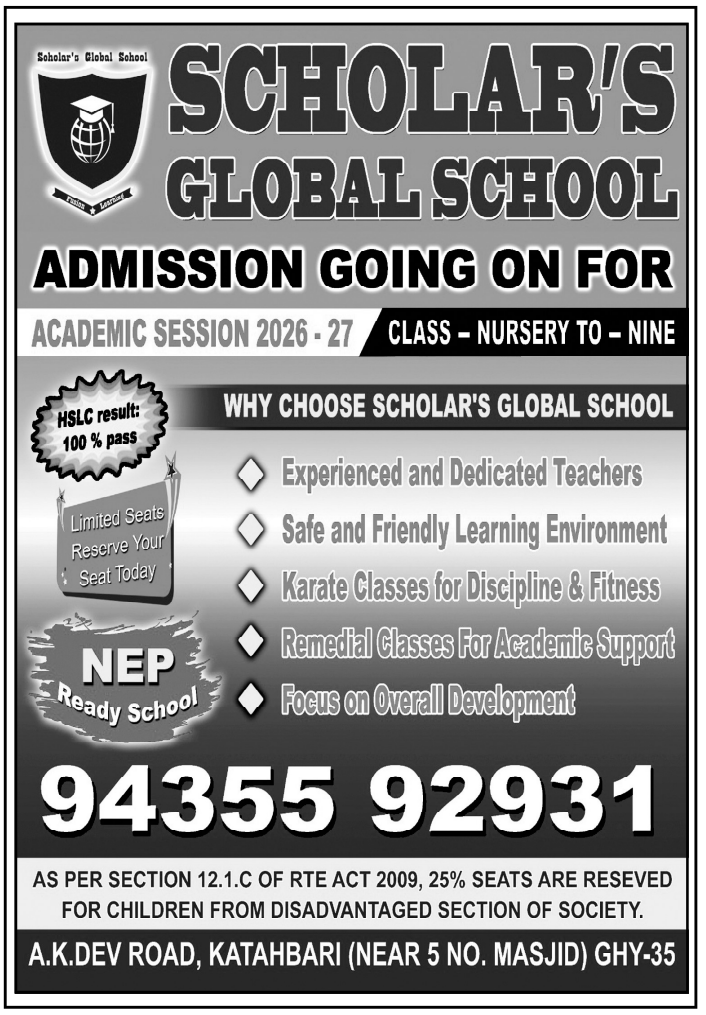

दलीप ट्रॉफी से शुरू होगा नया घरेलू क्रिकेट सीजन

दो चरणों में खेली जाएगी रणजी ट्रॉफी, जम्मू-कश्मीर पर रहेंगी नजरें

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सत्र की घोषणा कर दी है। इस बार का घरेलू सीजन 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होगा, जिसमें छह जोनल टीमें हिस्सा लेंगी। पूरे सत्र में पुरुष, महिला और आयु वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताओं को मिलाकर कुल 1788 मैच खेले जाएंगे।

घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को एक बार फिर दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर से नवंबर 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण जनवरी से फरवरी 2027 के बीच खेला जाएगा। बीच के समय में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी आयोजित की जाएगी।

इस बार रणजी ट्रॉफी में 32 टीमें एलीट ग्रुप और 6 टीमें प्लेट ग्रुप में खेलेंगी। पिछले सीजन में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर पहली बार रणजी चैंपियन बनी जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम पर इस बार भी क्रिकेट प्रेमियों की विशेष नजर रहेगी। रणजी विजेता जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के बीच ईरानी कप 1 अक्टूबर से खेला जाएगा।

महिला घरेलू क्रिकेट सत्र अक्टूबर-नवंबर में सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी से शुरू होगा। इसके बाद इंटर-जोनल प्रतियोगिताएं और एकदिवसीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। वहीं अंडर-23 और विश्वविद्यालय स्तर के टूर्नामेंटों में भी बदलाव किए गए हैं।

बीसीसीआई ने कहा है कि नए घरेलू सत्र का उद्देश्य खिलाड़ियों को सभी प्रारूपों में संतुलित अवसर देना और भारतीय क्रिकेट की मजबूत नींव तैयार करना है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जूनियर प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थलों और समय में भी बदलाव किया गया है।

भारतीय हॉकी में विदेशी बनाम स्वदेशी कोच पर विवाद

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारतीय हॉकी के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हॉकी इंडिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए विदेशी कोचों को प्राथमिकता देने की नीति पर खुलकर नाराजगी जताई है। जूनियर टीम के मुख्य कोच पद से हटाए जाने के बाद श्रीजेश ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या भारतीय कोच भारतीय हॉकी का विकास नहीं कर सकते?

दो बार ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रहे श्रीजेश ने कहा कि उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में जूनियर टीम को पांच टूर्नामेंट में पदक दिलाए, जिसमें जूनियर एशिया कप का स्वर्ण और जूनियर विश्व कप का कांस्य पदक शामिल है। इसके बावजूद उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया।

श्रीजेश ने आरोप लगाया कि हॉकी इंडिया जूनियर स्तर पर भी विदेशी कोच नियुक्त करना चाहती है। उन्होंने लिखा कि पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि खराब प्रदर्शन के कारण नहीं, बल्कि विदेशी कोच को लाने के लिए किसी भारतीय को हटाया जा रहा है।

हालांकि दिलीप तिर्की की अध्यक्षता वाली हॉकी इंडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि श्रीजेश का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो गया था और नए कोच का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया है। संस्था का कहना है कि श्रीजेश को भारत-ए टीम और सीनियर टीम के गोलकीपिंग कोच की पेशकश भी की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

विवाद के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब भारत के पूर्व खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिला चुके हैं, तो क्या भारतीय खेल संस्थाओं का भरोसा अब भी विदेशी कोचों पर ही टिका रहेगा?

उल्लेखनीय है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच दक्षिण अफ्रीका केक्रेग फुलटन हैं, जबकि महिला टीम की जिम्मेदारी नीदरलैंड के कोच के पास है।

पाक को धूल चटाकर डब्ल्यूटीसी में भारत से आगे निकला बांग्लादेश

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

सिलहट में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 78 रन से हराकर दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली हैं। बता दें कि बांग्लादेश ने इससे पहले भी 2024 में पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान का सूपड़ा साफ किया था और अब घरेलू मैदान पर भी लगातार दूसरी बार श्रृंखला जीत दर्ज की है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का बड़ा लक्ष्य मिला था। चौथे दिन तक मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की साझेदारी ने पाकिस्तान को मुकाबले में बनाए रखा था, लेकिन अंतिम दिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म कर दी।

बांग्लादेश की जीत के सबसे बड़े नायक बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम रहे हैं। उन्होंने दूसरी पारी में छह विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तोड़ दिया हैं। गौरतलब है कि अंतिम दिन ताइजुल इस्लाम ने दो महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिससे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है।

मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए संघर्ष जरूर किया और 94 रन की पारी खेली, लेकिन उन्हें शोरीफुल इस्लाम ने आउट कर दिया। रिजवान के आउट होते ही पाकिस्तान की हार लगभग तय हो गई थी। पाकिस्तान की पूरी टीम 358 रन पर सिमट गई।

इस मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से कप्तान शान मसूद, बाबर आजम और सलमान आगा ने भी उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन कोई बल्लेबाज टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सका हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश ने पूरे मैच में दबाव बनाए रखा और हर महत्वपूर्ण मौके पर विकेट निकालने में सफलता हासिल की है।

बता दें कि पहले टेस्ट में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हराया था। शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले के बाद सिलहट में भी बांग्लादेश ने दमदार प्रदर्शन दोहराया।

इस श्रृंखला जीत का असर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका पर भी पड़ा हैं। बांग्लादेश अब 58.33 प्रतिशत जीत अंक के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गया हैं, जबकि भारत छठे स्थान पर खिसक गया हैं। पाकिस्तान की टीम आठवें स्थान पर बनी हुई हैं।

गौरतलब है कि बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार सुधार करता दिखाई दे रहा हैं। घरेलू परिस्थितियों में उनकी स्पिन गेंदबाजी अब बड़ी टीमों के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी श्रृंखला जीत ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश अब एशियाई टेस्ट क्रिकेट में मजबूत दावेदार बन चुका हैं।

'दृश्यम 3' ने मचाया धमाल

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 3 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जॉर्जकुट्टी के किरदार में मोहनलाल की वापसी ने फैंस को रोमांचित कर दिया है। शुरुआती दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार फिल्म सस्पेंस, इमोशन और दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट से भरपूर है।

फिल्म के पहले शो के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों ने इसे 'सस्पेंस सिनेमा की मास्टरपीस' बताया। कई यूजर्स ने लिखा कि फिल्म का इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमेक्स इतना दमदार है कि दर्शकों की आंखें खुली रह जाती हैं। एक दर्शक ने लिखा, 'दृश्यम 3 उम्मीदों से कहीं आगे निकली। हर सीन आपको बांधे रखता है और क्लाइमेक्स पूरी कहानी को नए स्तर पर पहुंचा देता है।'

फिल्म में जॉर्जकुट्टी के नए संघर्षों को दिखाया गया है, जहां अतीत के फैसलों का बोझ और सच छिपाने की जंग पहले से ज्यादा जटिल रूप लेती दिखाई देती है। ट्रेलर में जिस भावनात्मक और रहस्यमयी माहौल की झलक मिली थी, फिल्म ने उसे और गहरा बना दिया है।

फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का मानना है कि दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी ने फिर साबित कर दिया कि सस्पेंस थ्रिलर के मामले में मलयालम सिनेमा का कोई मुकाबला नहीं है। कई फैंस इसे साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बता रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी
इंटरनेट पर मचा तहलका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब केवल चैटबॉट या फोटो एडिटिंग तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने दिखा दिया है कि एआई आने वाले समय में राजनीति, तकनीक और डिजिटल दुनिया का पूरा खेल बदल सकता है। महज चार दिनों में इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जुटाने वाली इस डिजिटल पार्टी ने अब अपनी एआई आधारित वेबसाइट बनाकर सबको चौंका दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के अनुसार उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से एक घंटे के भीतर पूरी वेबसाइट और एआई एंथम तैयार कर लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें पारंपरिक कोडिंग का लगभग इस्तेमाल ही नहीं हुआ।

अभिजीत दिपके ने एक इंटरव्यू में बताया कि ग्राफिक्स, डिजाइन और वेबसाइट लेआउट तैयार करने के लिए केवल एआई को निर्देश देना पड़ा और कुछ ही मिनटों में तैयार सामग्री सामने आ गई। यही वजह है कि बिना बड़ी टेक टीम और भारी खर्च के यह डिजिटल प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड गति से तैयार हो सका।

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार फ्रेमर एआई, डोरा, रिल्यूम डॉट आईओ और वी-जीरो डॉट डेव जैसे नए एआई टूल्स वेबसाइट निर्माण की दुनिया को पूरी तरह बदल रहे हैं। अब केवल एक टेक्स्ट आइडिया देकर वेबसाइट का डिजाइन, एनिमेशन और पूरा यूजर इंटरफेस तैयार किया जा सकता है।

गलत वॉकिंग स्टाइल से खराब हो सकता है पोश्चर और दिमाग

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

पैदल चलना सेहत के लिए सबसे बेहतरीन और आसान एक्सरसाइज माना जाता है। डॉक्टर से लेकर फिटनेस एक्सपर्ट्स तक, हर कोई रोजाना वॉक करने की सलाह देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से चलना आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय भारी नुकसान पहुंचा सकता है? जाने-अनजाने में की गई चलने की कुछ गलतियां आपके जोड़ों और पोश्चर पर बुरा असर डालती हैं।

बहुत धीरे-धीरे चलना

अगर आप वॉक के नाम पर सिर्फ धीमी गति से टहल रहे हैं, तो यह सेहत के लिए काफी नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि चलने की धीमी गति का सीधा संबंध डिमेंशिया के बढ़ते खतरे से हो सकता है। कई बार डिमेंशिया के लक्षण सामने आने से सालों पहले ही व्यक्ति की चलने की गति धीमी होने लगती है। इसलिए अपनी वॉक में थोड़ी तेजी लाएं, ताकि आपके दिल की धड़कनें बढ़ें और दिमाग को भी पूरा फायदा मिले।

हाथ में फोन लेकर चलना

आजकल लोग चलते समय भी लगातार फोन में रील्स स्क्रॉल करते हैं या टेक्स्टिंग करते हैं। यह आदत आपके पोश्चर का बिगाड़ कर रख देती है। जब आप नीचे स्क्रीन की तरफ देखते हुए चलते हैं, तो गर्दन, पीठ और कूल्हों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिससे दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा, नीचे देखने से आप गिरने या टकराने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, फोन में खोए रहने से आप कॉग्निटिव ब्रेक को मिस कर देते हैं, जो वॉक के दौरान तनाव कम करने के लिए जरूरी है।

आगे की तरफ झुककर चलना

घंटों ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने से हमारे हिप्स टाइट हो जाते हैं और पीठ का ऊपरी हिस्सा बाहर की ओर निकल जाता है। इसका असर हमारे चलने के तरीके पर भी दिखता है। कई लोग चलते समय अपने ऊपरी शरीर को निचले शरीर से आगे की तरफ झुका कर चलते हैं। वॉक करते समय बीच-बीच में अपने पोश्चर को चेक करते रहें। सीधे खड़े हों, कंधों को पीछे और ढीला रखें, और नजरें सामने रखें।

पैरों को घसीटकर चलना

कई लोगों की आदत होती है कि वे चलते समय पैरों को पूरा ऊपर नहीं उठाते, जिसे शफलिंग कहा जाता है। एक सही वॉक में पहले एड़ी जमीन को छूती है फिर पैर सीधा होता है, आगे रोल होता है और फिर अंगूठे से शरीर आगे पुश होता है। जब आप पैरों को घसीटकर चलते हैं, तो आपके ठोकर खाकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, पैर पटकने से टखने, घुटने और कूल्हे झटके को सोख नहीं पाते, जिससे जोड़ों में दर्द और खिंचाव हो सकता है।

हिप्स की मांसपेशियों का इस्तेमाल न करना

ज्यादातर लोग चलते समय जमीन को पीछे की तरफ धकेलते नहीं हैं। सही तरीका यह है कि आप अपनी ग्लूट मसल्स को एक्टिव करें। इसे सुधारने के लिए जब आप पैर आगे बढ़ाएं, तो जमीन पर टिके पैर से नीचे और पीछे की तरफ दबाव बनाएं। इससे ग्लूट्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे आपकी चाल में ताकत आएगी और जोड़ों पर दबाव कम होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार सही तरीके से की गई रोजाना 30 मिनट की वॉक न केवल वजन नियंत्रित रखती है, बल्कि दिल, दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होती है।

पूर्वांचल प्रिंट्स की ओर से राजनाथ पाल द्वारा जीएमसीएच रोड, हरबाला मार्केट, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005 से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपर्क : 69001 26012
ई-मेल:official.janjanvichar@gmail.com, वेबसाइट : www.janjanvichar.in
● कार्यकारी संपादक : सुभाष कुमार चौधरी ●संपादक : धनेश्वर चौधरी